तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव : 2020 में एक नये महानायक का उदय !

संपादक

एच.एल. दुसाध

चन्द्रभूषण सिंह यादव

तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव-2020 में
एक नए बहुजन नायक का उदय!

तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा चुनाव-2020 में
एक नए बहुजन नायक का उदय!

संपादक
एच. एल. दुसाध
चन्द्रभूषण सिंह यादव

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन
नई दिल्ली-110047

प्रथम संस्करण : 2021

प्रकाशक : **बहुजन डाइवर्सिटी मिशन**
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. 9654816191

© **लेखक**

मूल्य : 180.00 रुपये

रचना : तेजस्वी यादव :
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक नए बहुजन नायक का उदय
संपादक : एच. एल. दुसाध, चन्द्रभूषण सिंह यादव
शब्दांकन : कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
आवरण : राकेश यादव
मुद्रक : क्विक ऑफसेट, दिल्ली-110094

समर्पण

त्याग और ममता की अद्भुत मूर्ति
श्रीमती गंगा देवी कुशवाह
को सादर

अनुक्रम

संपादकीय 11

अध्याय-1 : चुनाव पर दुसाध **15**

बिहार विधानसभा चुनाव पर रहेगी : बीडीएम की निगाहें—17, भोपाल घोषणा का असर—18, कम्युनिस्ट घोषणापत्र पर भारी पड़ सकता है : बीडीएम का घोषणापत्र—18, भोपाल और बीडीएम के घोषणापत्र में मौलिक प्रभेद—19, डाइवर्सिटी से पनपने लगी है : सर्वत्र भागीदारी की चाह—20, पार्टियों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी—20, सवर्ण आरक्षण के बाद उज्ज्वलतर हुई : डाइवर्सिटी की सम्भावना—21, डाइवर्सिटी पहना सकती है बहुजनवादी दलों को ताज!—22, बिहार विधानसभा चुनाव पर रहेगी : बीडीएम की निगाहें—22, **मंडल उत्तरकाल में सामाजिक न्याय की ऐसी उपेक्षा कभी नहीं हुई**—23, बहुजन मुक्ति के सबसे बड़े मुद्दे की अनदेखी—30, 10 लाख नौकरियों के सामने : बाकी मुद्दे फेल—30, सबसे बड़ा मुद्दा : बहुजनों की गुलामी—30, मोदी का खतरनाक इरादा : बहुजनों को बदहाल एवं सवर्णों को खुशहाल बनाना—31, बहुजन नेताओं में न तो अपने समाज की गुलामी की समझ है और न मुक्ति की तड़प—32, **हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना से सावधान!**—33, तेजस्वी को रोकने के लिए : मोदी ने संभाला मोर्चा—33, संविधान : हिन्दू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ी बाधा—33, हिन्दू राष्ट्र के लिए : कोरोना काल का सद्व्यवहार—34, बिहार के गैर-सवर्ण मतदाताओं पर ऐतिहासिक जिम्मेवारी—36, **क्या लॉकडाउन की यंत्रणा को भूल पाएंगे बिहारवासी**—36, शुरू हुआ सड़कों का खून से रंगे जाना—36, लॉकडाउन में भारत की सड़कें बन गईं : जालियावालां बाग—37, रेल की पटरियों और सड़कों पर मरते रहे मजदूर—37, लॉकडाउन के पीछे रहे : मोदी के कुछ खास मकसद!—38, क्या लॉकडाउन की दुर्दशा का हिसाब चुकता करेंगे : बिहारी मजदूर—39, **बिहार चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा!**—40, नीतीश ने लगाया : सामाजिक न्याय का तड़का—40, सामाजिक न्याय क्या है—41, मंडलवादी आरक्षण से शुरू : वर्ग-संघर्ष!—42, शासकों की आरक्षण विरोधी मुहिम के खिलाफ उठा : सर्वव्यापी

आरक्षण वाली डाइवर्सिटी का मुद्दा—43, **डाइवर्सिटी से मिला : सामाजिक न्याय की लड़ाई का नया तेवर!**—44, डॉ आंबेडकर की 'राज्य और अल्पसंख्यक' के बाद बहुजनों की मुक्ति की सर्वोत्तम रचना : चंद्रभान प्रसाद का 'भोपाल दस्तावेज और भोपाल घोषणापत्र'!—44, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का 10 सूत्रीय एजेंडा!—45, डाइवर्सिटी से मिला सामाजिक न्याय का मुकम्मल सूत्र—45, आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी!—45, डाइवर्सिटी के रास्ते रचित हुये : सामाजिक न्याय के कुछ नए अध्याय!—47, बिहार के राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी!—48, बिहार विधानसभा चुनाव-2015 : निर्णायक बना डाइवर्सिटी का मुद्दा!—49, तो क्या नीतीश ने लालू की नकल किया है!—50, संख्यानुपात में आरक्षण : तेजस्वी के लिए साबित हो सकता है अचूक हथियार!—51, सिर्फ सामाजिक न्याय के जोर ही से रोका जा सकता है मोदी को!—51, **विकास के नाम पर वोट करने के पहले सोचें!**—53, नीतीश की भावुक अपील!—53, नीतीश की सत्ता से विदाई के संकेत!—53, विकास बनाम जंगलराज—54, सामाजिक न्याय के विरुद्ध : विकास का मुद्दा—55, विकास के खोखलापन को उजागर करती : डॉ. आंबेडकर की कसौटी—56, **और! तेजस्वी का तीर नहीं लगा निशाने पर!**—57, हतप्रभ करने वाला : चुनाव परिणाम—57, एग्जिट पोल में उभरी थी : तेजस्वी के जीत की संभावना—58, एग्जिट पोल्स पर : ललन कुमार की चौकाने वाली राय—58, ललन कुमार ने बढ़ाया : चुनाव परिणाम को लेकर दुश्चिन्ता!—59, भाजपा के घोषणापत्र में डाइवर्सिटी!—61, और ललन की भविष्यवाणी सही हो गई—63

अध्याय-2 : चुनाव पर चन्द्रभूषण सिंह यादव 65

तेजस्वी यादव की कन्सट्रक्टिव सोच—67, जेपी-वीपी सिंह को मात देती : तेजस्वी यादव की रैलियां—68, तेजस्वी यादव जी बिहार की आस व उम्मीद...—69, तेजस्वीमय होता बिहार—70, उन्नत बिहार को हमें है बनाना, लालू के लाल तेजस्वी ने ठाना—71, तेजस्वी यादव को देखने नहीं, सुनने के लिए जुटी है भीड़—72, तेजस्विता के आगे बड़े-बड़े शूरमा धाराशायी...—73, राजनैतिक पिच पर : छक्के छुड़ाते तेजस्वी—75, कब तक लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेते रहेंगे?—76, अब बात मुद्दों की होगी, लफ्फाजी के दिन गए...—78, बिहार में बहार बा, खाली भ्रष्टाचार बा, एकरा के हटावे के दरकार बा...—79, बिहार के विकास का विजन ले : जन अदालत में तेजस्वी—80, तेजस्वी की 10 लाख सरकारी नौकरी बनाम मोदी जी का ढपोरशंखी—81, गालियों से बेपरवाह : मुद्दों की राजनीति में मस्त तेजस्वी—83, जनसमुद्र में तब्दील होती : तेजस्वी की—84, 'लालटेन' जलाइए-यदि नीतीश कुमार जी व एनडीए का यही मंगल राज है तो बदल डालिये इस मंगल राज को....—85, तेजस्वी यादव : राजनीति का दुरूह व अलबेला पहलवान—87, मोदी बनाम तेजस्वी के मामले में फैसला तेजस्वी के पक्ष में होता दिख रहा है...—88, तेजस्वीमय बिहार का गवाह बनने पटना, दरभंगा से मधेपुरा तक की चुनावी यात्रा पर...—89, लालू जी ने सामाजिक न्याय दिलाया,

हम आर्थिक न्याय दिलाएंगे-तेजस्वी यादव—90, लालू राज 'जंगल राज' नहीं बल्कि बहुजनों का 'मंगलराज' था...—91, तेजस्वी यादव जी का 'दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्यवाही' का मंत्र बिहारियों को भा गया...—93, पोलिंग के बाद काउंटिंग के आये परिणामों के निहितार्थ...—94, तेजस्वी को हराने में पौराणिक अभिमन्यु की कथा दुहराया है एनडीए ने...—97, जरूरत लोकतंत्र की हत्या के दुष्प्रयास से लड़ने की है—98, नीतीश जी की ताजपोशी के साथ बिहार में नई संभावनाओं का गला घुंट गया...—99, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय—102

अध्याय-3 : फेसबुक पर चुनाव परिणाम **105**

सवर्णों को साधने में सत्ता फिसल गई—107, हारकर भी जीते नीतीश, जीतकर भी हार गए तेजस्वी—108, तेजस्वी के लिए सब कुछ अनुकूल था लेकिन...—110, बिहार और हम सबकी बौद्धिक और वैचारिक जीत हुई है!—110, जंगलराज बनने से बच गया बिहार—111, चापलूसों से घिरे तेजस्वी—112, मोदी विजय का खुला रहस्य—113, तेजस्वी के लिए सकारात्मक रहा चुनाव—114, ये रिजल्ट रिजेक्ट करता हूँ—114, 'बिहार महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस क्यों?'—115, महागठबंधन हारा नहीं, हराया गया है—115, तेजस्वी यादव बन गये जनाधार वाले जननेता—116, वामदलों को बेस्ट परफॉर्मर होने की बधाई!—116, ठीके तो हैं नीतीश कुमार—117, दो मुँहें हैं भाजपा नेता—117, जदयू की ऐतिहासिक दुर्गति—118, डीयू गुरु कहां है—118, ये मोदी की जीत है—119, बिहार चुनाव 2020 का संदेश—119, तेजस्वी का उभार बहुत कुछ कह रहा है—120, हेराफेरी और प्रपंच से बन रही सरकार—121, तेजस्वी ने खुद को साबित किया—121, तेजस्वी ने दाढ़ी वालों के नाकों चने चबवा दिये—122, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य...—123, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई!—124, CM अपनी शर्तों पर ही बनना चाहिए—124, राजद वाले परेशान—124, नीतीश हारे नहीं घेरे गए...—125, तेजस्वी एक नेता के रूप में स्थापित हुए—126, नीतीशजी के लिए प्रायश्चित का यही समय है!—126, भारत में सांप्रदायिक राजनीति और इवीएम के खेल ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी अब नीतीश पर है—127, तेजस्वी का जनता से जुड़ाव किसी जादू से कम नहीं—128, तेजस्वी और वामपंथियों को मिला : दुर्लभ अवसर—130, यही बिहार विधानसभा किस जाति का कितना पहुंचा प्रतिनिधि—132, तेजस्वी यादव के नाम पत्र—134, बिहार चुनाव परिणामों ने मेरा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया...—136, सामाजिक न्याय के मुद्दे को ताक पर रख दिया गया—137, बिहार में महाजंगलराज की शुरूआत हो चुकी है—137, चुनाव परिणाम पर दुसाध!—139, तेजस्वी की हार से आहत हूं, विस्मित नहीं—141, भाजपा के समक्ष हारने के लिए : क्यों विवश हैं बहुजनवादी दल!—141, मुश्किल है सवर्णों को मोदी से विमुख करना—142

अध्याय-4 : साक्षात्कार **143**

साक्षात्कार की प्रश्नावली 145

प्रश्नोत्तर

डॉ. प्रकाश ठाकुर 147
डॉ. अजय चौधरी 148
डॉ. सुनीता 149
डॉ. अनिल कुमार 149
बुद्ध शरण हंस 151
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण 153
डॉ. जनमेजय 154
जनार्दन 156
शीलबोधी 157
मनीषा गौतम 158
अरुण कुमार पासवान 158

संपादकीय

दूसरे राज्यों के मुकाबले मुझे बिहार का चुनाव सर्वाधिक आकर्षित करता रहा है, क्योंकि चुनावों में अकसर यहाँ सामाजिक न्याय का मुद्दा हावी रहता है। इसी उम्मीद में मैंने 2010 में डाइवर्सिटी एजेंडे को पार्टियों के घोषणापत्रों में शामिल करवाने के लिए बिहार के मेजर 18 जिलों का दौरा कर 16 प्रेस कांफ्रेंस करने के साथ ही उतने ही छात्रावासों में छात्रों को संबोधित किया एवं उनके मध्य कई हजार पम्फलेट बांटे। यही नहीं उस चुनाव के पूर्व अप्रैल में 6 दिवसीय डाइवर्सिटी यात्रा भी निकाला। इन सारे अनुभवों को समेटने के लिए प्रो. आरबी मौर्य और बुद्ध शरण हंस साहब के साथ मिलकर **'विकसित बिहार का सपना और विधानसभा चुनाव-2010 के मुद्दे'** जैसी किताब लाया। और 2015 के चुनाव का क्या कहना! उस चुनाव के पूर्व 2014 के अगस्त में अनुष्ठित 10 सीटों के उपचुनाव में जिस तरह लालू जी ने सरकारी ठेकों सहित विकास की तमाम योजनाओं एससी, एसटी, ओबीसी और अकलियतों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण की आवाज उठाया और 2015 के चुनाव में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा सम्बन्धी बयान के जिस तरह बिहार के गाँव-गाँव तक यह सन्देश जोर-शोर से पहुचाया, **'तुम आरक्षण का खात्मा चाहते हो और हम सत्ता में आएंगे तो सबको संख्या अनुपात में हर क्षेत्र में आरक्षण देंगे',** उससे सामाजिक न्याय का मुद्दा तुंग पर पहुच गया। ऐसे में जब चुनाव परिणाम सामने आया मैंने उसे यादगार बनाने के लिए निकाली, **'बिहार विधानसभा चुनाव 2015 : मंडल के लोगों ने फोड़ दिया कमंडल'!** हालांकि 2020 के चुनाव में जिस तरह सामाजिक न्याय के मुद्दे की उपेक्षा हुई, उससे भारी निराशा मिली, किन्तु जिस तरह तेजस्वी यादव की सभाओं में जेपी और बीपी सिंह की ऐतिहासिक सभाओं को म्लान करने वाली भीड़ उमड़ी, उसे देखते हुए चुनाव परिणाम आने के बहुत पहले ही प्रखर चिन्तक चन्द्रभूषण सिंह यादव के साथ मिलकर इस चुनाव पर किताब लाने की घोषणा सोशल मीडिया पर कर दिया, जिसका परिणाम यह पुस्तक है।

2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें बहुत कम लोगों को लगता रहा कि तेजस्वी यादव एक कद्दावर नेता के रूप में उभरेंगे, किन्तु सबको

चौकाते हुए, वह एक महानायक के रूप में उभरे। चुनाव शुरू होने के पहले सभी लोगों, यहां तक कि सामाजिक न्याय के एकनिष्ठ समर्थकों तक को भी लगता था कि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में मोदी- नीतीश का एनडीए बड़े आराम से चुनाव जीत जाएगा। किन्तु आमजन सहित राजनीति के पंडितों तक को विस्मित करते हुए तेजस्वी यादव ने खुद के बूते चुनावी फ़िज़ा को बदल कर रख दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उन्होंने महागठबंधन के नेता के तौर पर अपनी भाषा, अपने नारों और अपनी शैली से चुनावी राजनीति के स्थापित व्याकरण को बदल कर रख दिया। फलतः मोदी- नीतीश का मोर्चा उद्‍भ्रांत होकर पूरे चुनाव भर तेजस्वी की काट ढूंढने में व्यस्त रहा पर, सफल होता नहीं दिखा। इसीलिए चुनाव खत्म होने के बाद जब एग्जिट पोल की रिपोर्ट सामने आई, देखा गया कि प्रायः सभी ने ही भारी अंतर से महागठबंधन के विजयी होने के संभावना जाहिर किया। यह बात और है जब चुनाव परिणाम सामने आया, शुरुआत में ही एग्जिट पोल के मुताबिक विजय की संभावना दिखाकर महागठबंधन अंत में कांटे के मुकाबले में नाटकीय रूप से हार वरण करने के लिए विवश हुआ। किन्तु स्तब्धकारी हार के बावजूद तेजस्वी भविष्य के एक बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में सफल रहे। सच पूछा जाय तो बहुजन नजरिये से बिहार विधानसभा चुनाव- 2020 की सबसे बड़े उपलब्धि तेजस्वी के रूप में एक विराट संभावनापूर्ण नेता का उभार रहा।

बहरहाल बिहार चुनाव में भारी उम्मीद जगाकर तेजस्वी यादव क्यों शेष लक्ष्य भेदने में विफल रहे, इसे समझने के लिए अध्याय 3 और 4 अर्थात क्रमशः 'फेसबुक पर चुनाव परिणाम' और 'साक्षात्कार' में देश के जाने माने राजनीति विज्ञानियों, साहित्यकारों की राय सुलभ करायी गयी है। इसलिए बिहार विधानसभा-2020 को ठीक से समझने के लिए इन दोनों अध्यायों को विशेष मनोयोग पूर्वक पढ़े जाने की गुजारिश करता हूँ। इन अध्यायों में सामाजिक न्याय विरोधी खेमे के लोगों को भी जगह दी गयी है। सच कहूं तो यही दो अध्याय इस पुस्तक के प्राण हैं। अध्याय 3 की शुरुआत ही स्त्री - काल के संपादक sanjeev chandan सवर्णों को साधने में सत्ता फिसल गई से हुई है। चन्दन पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने चुनाव शुरू होने के पहले महागठबंधन की ओर से सामाजिक न्याय की उपेक्षा तथा के ए टू जेड फार्मूले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अपने चैनल स्त्री-काल के कई एपिसोड इसी बात पर केन्द्रित कर तेजस्वी यादव को सावधान करने की कोशिश की। यही नहीं उन्होंने भी प्रख्यात पत्रकार urmilesh जी की भांति ही कांग्रेस को कमजोर कड़ी बताया। urmilesh की भांति girish malviya ने इस परिणाम के लिए कांग्रेस को मुख्य रूप से जिम्मेवार ठहराया है। उनका मानना है कि तेजस्वी के साथ वाम दलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया पर, नहीं कर सकी तो कांग्रेस, जो 70 में से 51 सीटें हार गयी। मालवीय जी ने एक बड़ी खास बात यह कही है,' इस चुनाव का सबसे त्रासद अनुभव

यह था कि हमने लॉकडाउन के दौरान हजारों-लाखों बिहारी मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में पलायन करते देखा और गाँव पहुंच कर वे लोग उसी भाजपा को अपना वोट दे आये जिसने लॉकडाउन जैसा निर्णय लिया ...'। वास्तव में लॉक डाउन में घर लौटे प्रवासी बिहारी मजदूरों ने वोटर के रूप में अपने व्यवहार से लोगों को चौकाया है। बहरहाल manish ranjan reborn, jayant jigyasu जैसे कई लोगों को लगता है प्रशासन और इवीएम की मदद से तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोका गया है। तेजस्वी यादव की नैया किनारे पर जाकर क्यों डूबी, इसे जानने में नवल किशोर कुमार, piyush raj, ranjan yadav, premkumar mani, drmanraj shastri, mohan singh, harikeshvar ram, jitendra narayan, lal babu lalit, shankar pralami, rakesh sammauria, amar azad इत्यादि के विचार पाठकों के लिए काफी मददगार साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है।

जहाँ तक सवर्णवादी नजरिये का सवाल है, उसका बेहतरीन प्रतिबिम्बन सोनाली मिश्र और krishna mishra की टिप्पणियों में हुआ है। सोनाली मिश्रा ने अपनी बड़ी सी टिपण्णी में बिहार की जनता, खासकर महिलाओं के प्रति आभार जताया है कि उन्होंने जाति से परे होकर बिहार को जंगलराज होने से बचा लिया। वहीं krishna mishra की राय है कि मोमिनों के ब्रेनवाश का शिकार इक्का-दुक्का उदाहरणों को छोड़कर अनुसूचित जाति-जनजाति के हर सदस्य को अपना धर्म उतना ही प्यारा है, जितना किसी सवर्ण को। और अपने धर्म के पालन की गारंटी उन्हें केवल मोदी की छत्रछाया में ही दिखती है। यही कारण है कि मोदी को across the caste line वोट मिलते हैं। बहरहाल अध्याय 3 और 4 में अधिकांश विद्वानों की जो राय सामने आई है उसका निष्कर्ष यह है कि मुख्यतः सामाजिक न्याय की अनदेखी के कारण ही तेजस्वी यादव की नैया किनारे जाकर डूब गयी। सवर्णों का समर्थन पाने के लिए तेजस्वी ने सामाजिक न्याय की पूर्णतया अनदेखी करने के साथ 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर दुनिया का ध्यान जरुर आकर्षित किया, किन्तु, सवर्ण मतदाताओं पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। इससे यह सिद्ध हो गया कि सवर्ण किसी भी सूरत में मोदी का साथ नहीं छोड़ सकते।

बहरहाल अध्याय 3 और 4 में आई विद्वानों की राय से खूब अलग मेरी भी राय नहीं है, यह 136 से 140 पर प्रकाशित 'चुनाव परिणाम पर दुसाध' पढने पता चल जायेगा। अगर थोड़े में नए सिरे से कहना हो तो यही कहूँगा कि तेजस्वी यादव की नैया किनारे जाकर इसलिए डूबी, क्योंकि वह बिहार विधानसभा चुनाव-2020 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के उस हथियार को बिलकुल विस्मृत कर गये, जिसके जोर से उन्होंने 2015 में अप्रतिरोध्य बने मोदी को शर्मनाक हार झेलने के लिए विवश किया था। लालू प्रसाद यादव का वह हथियार था डाइवर्सिटी अर्थात सर्वव्यापी आरक्षण! हाँ, 2015 में जब मोहन भागवत ने आरक्षण के समीक्षा की बात कही, तब

लालू जी ने कहा था,' तुम आरक्षण के खात्मे की बात करते हो, हम सत्ता में आयेंगे तो लोगों को हर क्षेत्र में संख्यानुपात में आरक्षण देंगे।' उनके द्वारा सर्वव्यापी आरक्षण का मुद्दा जोर-शोर उठाये जाने के कारण बाज़ी पलट गयी और मोदी करारी हार झेलने के लिए बाध्य हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी 2015 वाले लालू जी के हथियार (सर्वव्यापी आरक्षण) को याद रखें इसके बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के पिछले स्थापना दिवस अर्थात 15 मार्च, 2020 को **बिहार विधानसभा चुनाव पर रहेगीः बीडीएम् की निगाहें** (पृ-12) से एक अपील की गयी। तेजस्वी बहुजनों की गुलामी को मुख्य मुद्दा बनाकर सर्वव्यापी आरक्षण को एजेंडा बनायें, इसके लिए 8 सितम्बर,2020 को **'भविष्य का चुनावी मुद्दाः बहुजनों की मुकम्मल आजादी'** शीर्षक से फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर उन तक सन्देश पहुचाने का प्रयास हुआ। फिर 23 अक्तूबर, 2020 को लालू जी का 2015 का कारनामा याद दिलाने के लिए ही फेसबुक पर यह पोस्ट डाला—**मुद्दा ऐसा हो कि लोग कमंडल फोड़ने पर आमादा हो जायें।** बाद में जब चुनाव का विगुल बज गया 28 अक्तूबर से 12 नवम्बर, 2020 के मध्य 7 बड़े-बड़े लेख लिखा (देखें अध्याय-1)। बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुजनों की गुलामी और उनकी आजादी के लिए सर्वव्यापी आरक्षण का मुद्दा न उठाकर एक बड़ा अवसर गँवा दिया।

हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे के तहत मोदी जिस तरह बहुजनों को गुलामों की स्थिति में पहुंचा दिए हैंः 1-9 तक गुलामी से मुक्ति ही बहुजनों का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इन पंक्तियों के लिखे जाने के दौरान एक अख़बार में खबर छपी है कि संघ लोकसेवा आयोग ने लैटरल इंट्री के जरिये संयुक्त सचिव और निदेशक पद के लिए कुल 30 पदों की जो वैकेंसी निकाली है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आवेदन करने की मनाही कर दी गयी है। यह इस बात का संकेतक है कि देश में हिन्दूशाही पूरी तरह कायम हो चुकी है और बहुजन उन सब कामों से रोके जायेंगे जो पेशे/कर्म हिन्दू धर्म में सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित रहे। ऐसे में बहुजनों को गुलामी से मुक्ति की लड़ाई में उतरने से भिन्न क्या कोई विकल्प रह गया है? अंत में! अशेष आभार साथी चन्द्रभूषण सिंह यादव सहित उन समस्त विद्वानों को जिनके साक्षात्कार और फेसबुक पर आये विचारों से यह पुस्तक समृद्ध हुई है। बतौर संपादक अपनी बात समाप्त करने से पहले एक खास अनुरोध करना चाहूँगा, वह यह कि पृ-132 पर प्रकाशित laxaman yadav का **तेजस्वी यादव के नाम पत्र** अवश्य ही एकाधिक बार मनोयोग पूर्वक पढ़ें!

जय भीम! जय भारत!

15 मार्च, 2021
(बीडीएम का 15वां स्थापना दिवस)

—एच.एल. दुसाध
(संस्थापक अध्यक्ष, बीडीएम)

अध्याय-1

चुनाव पर दुसाध

बिहार विधानसभा चुनाव पर रहेगी : बीडीएम की निगाहें

–एच.एल. दुसाध

आज 15 मार्च है। आज ही के दिन 2007 में भोपाल घोषणापत्र से प्रेरित होकर प्रो. वीरभारत तलवार, प्रो.कालीचरण, प्रो. संजय पासवान,मास्टर मानसिंह, आरसी भाषकर, इंजी बृजपाल भारती, डॉ.दिनेश राम इत्यादि की उपस्थिति में उ.प्र. के आगरा में बहुजन लेखकों का संगठन 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' वजूद में आया और देखते ही देखते एक दशक के मध्य ख़ामोशी से बड़े बदलाव की वैचारिक जमीन तैयार दिया। आज यह संगठन साहित्य के लिहाज से देश के समृद्धतम संगठनों में से एक बन चुका है। इस संगठन से जुड़े लेखकों ने डाइवर्सिटी के मुद्दे पर 85 से अधिक किताबें तैयार किया है, जिनमें 75 के करीब किताबें खुद इस लेखक की हैं। आरक्षण के खात्मे से त्रस्त होकर जिन दिनों बहुजन एक्टिविस्ट आरक्षण बचाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग बुलंद कर रहे थे, उन्ही दिनों 2002 के 12-13 जनवरी को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सौजन्य से भोपाल में दलितों का ऐतिहासिक सम्मलेन आयोजित हुआ। सम्मलेन के शुरू में भोपाल दस्तावेज और शेष में भोपाल घोषणापत्र (21वीं सदी में दलितों के लिए नयी रणनीति) जारी हुआ था। चंद्रभान प्रसाद द्वारा लिखित भोपाल दस्तावेज और भोपाल घोषणापत्र में दलितों (एससी/एसटी) के अतीत और वर्तमान की आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, शैक्षिक अवस्था का निर्भूल विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए इक्कीसवीं सदी में भूमंडलीकारण के सैलाब में दलितों को तिनकों की भांति बहने से बचाने के लिए 21 सूत्रीय दलित एजेंडा प्रस्तुत किया गया था, जो इतिहास में भोपाल घोषणापत्र के नाम से जाना जाता है। भोपाल घोषणापत्र में अमेरिका के सर्वव्यापी आरक्षण वाली डाइवर्सिटी से प्रेरित होकर एससी/एसटी के लिए नौकरियों से आगे बढ़कर सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों,फिल्म-मीडिया इत्यादि सहित धनार्जन के समस्त स्रोतों में संख्यानुपात में आरक्षण दिलाने का ही एजेंडा पेश किया गया था। इस क्रान्तिकारी घोषणापत्र से तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 25 जनवरी, 2002 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में इसे अपनाने के लिए राष्ट्र के

समक्ष अपील कर डाली थी। भोपाल घोषणापत्र दलितों में उद्योगपति, सप्लायर, डीलर, ठेकेदार इत्यादि बनने की महत्वाकांक्षा उभारने के भरपूर तत्व थे। महत्वाकांक्षा का यह उभार राजनीति में झंझावती परिणाम ला सकता है, ऐसी आशंका इसके जारी होने के बाद देश के ढेरों विद्वानों ने जाहिर की थी।

भोपाल घोषणा का असर

बहरहाल भोपाल घोषणा के क्रान्तिकारी एजेंडे ने तो तत्कालीन राष्ट्रपति, प्राख्यात विद्वानों सहित पूरे राष्ट्र के दलितों को स्पर्श किया, किन्तु किसी को भी यकीन नहीं था कि भारत में भी अमेरिका की भांति सप्लाई, डीलरशिप,ठेकों इत्यादि में आरक्षण लागू हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने 27 अगस्त,2002 को अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग में एससी/एसटी के लिए कुछ वस्तुओं की सप्लाई में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिखा दिया कि यदि सरकारों में इच्छा शक्ति हो तो अमेरिका की तरह भारत के वंचितों को भी उद्योग-व्यापार में अवसर सुनिश्चित कराया जा सकता है। दिग्विजय सिंह के उस ऐतिहासिक कदम से आरक्षण के खात्मे की आशंका से भयाक्रांत दलितों में यह विश्वास जन्मा कि एक दिन उन्हें भी अमेरिका के अश्वेतों की भांति नौकरियों से आगे बढ़कर उद्योग-व्यापार इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी मिल सकती है। फिर तो ढेरों दलित नेता और संगठन अपने-अपने तरीके से डाइवर्सिटी आन्दोलन को आगे बढाने में जुट गए। नेताओं में जहां डॉ.संजय पासवान ने इस मुद्दे पर पहली बार संसद का ध्यान आकर्षित करने के बाद कई संगोष्ठियां आयोजित की, वहीं बीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के.चौधरी ने 'निजी क्षेत्र में आरक्षण, अमेरिका के डाइवर्सिटी पैटर्न पर' को अपनी राजनीतिक पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा बना कर डाइवर्सिटी के पक्ष में अलख जगाना शुरू किया। इस मामले में डॉ. उदित राज भी खूब पीछे नहीं रहे। भोपाल घोषणा से प्रेरित हो देश भर के ढेरों दलित संगठनों ने अपने-अपने राज्य सरकारों के समक्ष डाइवर्सिटी मांग-पत्र रखा।

कम्युनिस्ट घोषणापत्र पर भारी पड़ सकता है : बीडीएम का घोषणापत्र

लेकिन कुछ ही वर्षो में जब डाइवर्सिटी की मांग उठाने वाले संगठनों और नेताओं की गतिविधियां धीमी पड़ने लगीं। वैसी स्थिति में डाइवर्सिटी के विचार को आगे बढ़ने के लिए इस लेखक की अध्यक्षता में 15 मार्च,2007 को बहुजन लेखकों के संगठन 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन'(बीडीएम) की स्थापना हुई। इस अवसर पर बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का 64 पृष्ठीय घोषणापत्र जारी हुआ। 'भोपाल घोषणापत्र' के बाद बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणापत्र एक बेहद महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहा, इसका अनुमान सुप्रसिद्ध बहुजन लेखक डॉ. विजय कुमार त्रिशरण की इस टिपण्णी से लगाया

जा सकता है-'एच.एल.दुसाध द्वारा लिखा गया बीडीएम का घोषणापत्र बहुजन समाज के उत्थान और उद्धार का एक मन्त्र संहिता है। इस बहुजन मुक्ति संहिता में कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र से भी ज्यादा आग है। यदि गहरी निद्रा में सुषुप्त हमारे समाज के लोगों में थोड़ी भी गर्माहट पैदा हुई तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीडीएम् का घोषणापत्र एक दिन कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर भारी पड़ेगा' (डॉ.विजय कुमार त्रिशरण,आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी खंड-2, पृष्ठ-59)'

भोपाल और बीडीएम के घोषणापत्र में मौलिक प्रभेद

भोपाल और बीडीएम के घोषणापत्र, दोनों में ही धनार्जन के समस्त स्रोतों में हिस्सेदारी की राह सुझाई गयी थी, पर, दोनों में मौलिक प्रभेद यह था कि भोपाल घोषणा में डाइवर्सिटी की मांग सिर्फ एससी/एसटी के लिए थी, किन्तु बीडीएम से जुड़े लेखकों ने इसका विस्तार शक्ति के समस्त स्रोतों में सभी सामाजिक समूहों के स्त्री-पुरुषों तक कर दिया। चूंकि मिशन से जुड़े लोगों का यह दृढ मत रहा है कि आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी ही मानव-जाति की सबसे बड़ी समस्या है तथा शक्ति के स्रोतों(आर्थिक-राजनीतिक- धार्मिक-शैक्षिक)में सामाजिक (social) और लैंगिक (gender) विविधता (diversity) के असमान प्रतिबिम्बन (reflection) से ही सारी दुनिया सहित भारत में भी इसकी उत्पत्ति होती रही है, इसलिए ही बीडीएम ने शक्ति के सभी स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन कराने की कार्य योजना बनाया। ऐसे में मिशन के तरफ से निम्न क्षेत्रों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन कराने अर्थात विविधतामय भारत के चार सामाजिक समूहों-सवर्ण,ओबीसी,एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों- के स्त्री-पुरुषों की संख्यानुपात में अवसरों के बंटवारे की निम्न दस सूत्रीय कर्मसूचियां स्थिर किया गया-:

1- सेना व न्यायालयों सहित सरकारी और निजीक्षेत्र की सभी स्तर की,सभी प्रकार की नौकरियों व धार्मिक प्रतिष्ठानों; 2- सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा दी जानेवाली सभी वस्तुओं की डीलरशिप; 3- सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा की जानेवाली सभी वस्तुओं की खरीदारी; 4- सड़क-भवन निर्माण इत्यादि के ठेकों,पार्किंग,परिवहन; 5- सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाये जानेवाले छोटे-बड़े स्कूलों, विश्वविद्यालयों,तकनीकि-व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संचालन,प्रवेश व अध्यापन; 6- सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा अपनी नीतियों,उत्पादित वस्तुओं इत्यादि के विज्ञापन के मद में खर्च की जानेवाली धनराशि; 7- देश-विदेश की संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को दी जानेवाली धनराशि; 8- प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं फिल्म-टीवी के सभी प्रभागों; 9- रेल-राष्ट्रीय मार्गों की खाली पड़ी भूमि सहित तमाम सरकारी और मठों की खाली पड़ी जमीन व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अस्पृश्य-आदिवासियों में वितरित हो एवं 10- ग्राम-पंचायत, शहरी निकाय, संसद-विधासभा

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

• Curate diverse book collections
• Support authors from marginalized communities
• Provide free resources to educators
• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library